



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 151] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1971/फाल्गुन 4, 1892

No. 151] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1971/PHALGUNA 4, 1892

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रकाश संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING  
AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 23rd February 1971*

S.O. 923.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply, distribution and transmission of electrical energy to the public and the maintenance of operational efficiency within the areas of, or served by, the municipal electrical undertakings at Madurai, Coimbatore, Karur, Thanjavur and Pollachi in the State of Tamil Nadu would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. N.11017/3/71-LSG.]

( 1239 )

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1971

एस० ओ० 923.—प्रतिवार्य सेवा में अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (I) क खण्ड (ए) की उपखण्ड (IX) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तमिलनाडु राज्य में मदुराई, कोयम्बटूर, करूर, तंजावुर और पोलाची में नगर पालिका बिजली उपक्रमों के क्षेत्र या उनसे संवित क्षेत्रों के अन्तर्गत जन सामान्य को बिजली की पूर्ति, वितरण और संचरण तथा उनके परिचालन कुशलता की देखरेख से सम्बन्ध सेवा में हड़ताल से जन समुदाय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोजनों के लिए अनेक ऐसी सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित किया जाता है ।

[सं० एन० 11017/3/71-स्वा० शा०]

#### ORDER

**S.O. 924.**—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service connected with the supply, distribution and transmission of electrical energy to the public and the maintenance of operational efficiency within the areas of, or served by, the municipal electrical undertakings at Madurai, Coimbatore, Karur, Thanjavur and Pollachi in the State of Tamil Nadu, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) No. S.O. dated the February, 1971, to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. N.11017/3/71-LSG.]

By order and in the name of the President.

A. B. MALIK, Joint Secy.

एस० ओ० 924.—यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जन हित में निम्नलिखित आदेश देना आवश्यक है ।

अतः, अत्र, अनिवार्य सेवा में अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु राज्य में मदुराई, कोयम्बटूर, करूर, तंजावुर और पोलाची के नगर पालिका बिजली उपक्रमों के या उनसे सेवित क्षेत्रों के अन्तर्गत जन सामान्य को बिजली की पूर्ति, वितरण कुशलता की देख-रेख

मेम्वद और संचरण सेवाओं में एतद्द्वारा हडतालों का निषेध करती है जिन्हें भारत सरकार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की संख्या                      दिनांक                      फरवरी, 1971 की अधिसूचना में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है।

[सं० एन० 11017/3/71-स्वा० शा०]

आदेशानुसार तथा राष्ट्रपति के नाम पर

अभिय भूषण मलिक, संयुक्त सचिव।

